# दो महीने में कोरोना ड्यूटी में लगे 726 शिक्षकों की मौत, 2845 संक्रमित

**सिस्टम में लापरवाही का संक्रमण...** फिर भी सरकार इन्हें नहीं मान रही कोरोना वॉरियर्स; न इलाज में सरकारी मदद और न मुआवजे का प्रावधान

## छिंदवाड़ा में सर्वाधिक 83 शिक्षकों की मौत, उज्जैन में 61 और सिवनी में 47 मौतें

**भास्कर न्यूज** | भोपाल. प्रदेशभर में कलेक्टरों के निर्देश पर कोविड ड्यूटी में जुटे करीब साढ़े चार हजार शिक्षकों में से बीते दो माह में 726 की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। जबकि 2845 शिक्षक संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी सरकार इन्हें कोरोना वॉरियर नहीं मानती। क्योंकि शिक्षक राज्य सरकार की कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल नहीं हैं, ऐसे में न तो उन्हें इलाज के लिए सरकारी मदद ही ठीक से मिल पा रही है, न ही परिजनों को नौकरी या मुआवजा मिल पाएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के अफसर भी घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि मृत शिक्षकों की संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो सकती है। मदद नहीं मिलने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

शेष|पेज 8 पर

## ट्रैकिंग सिस्टम पर अटकी सरकार

*कोरोना से शिक्षकों की मौतें हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। विभाग ने जान गंवाने वालों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। ताकि परिवार को तत्काल पेमेंट हो सके।*

**- रश्मि अरुण शमी,** प्रमुख सचिव

### इन जिलों में सर्वाधिक शिक्षक संक्रमित

### किस वर्ग के कितने कर्मचारी संक्रमित

| वर्ग | संक्रमित | निधन |
|---|---|---|
| अधिकारी | 29 | 3 |
| कर्मचारी | 136 | 44 |
| प्राचार्य | 119 | 24 |
| शिक्षक | 2561 | 655 |

Badri Gautam

## दो महीने में कोरोना...

गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूल टीचर और प्रिंसिपल्स को डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, सैंपल कलेक्शन, जांच केंद्र, कंटेनमेंट एरिया के सुपरविजन और चेक पोस्टों में यात्रियों व वाहनों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। कई जिलों में बड़े अस्पतालों में आरआई-पटवारी के साथ भी इन्हें तैनात किया गया है। भोपाल एम्स में स्टाफ की कमी के चलते छह सहायक शिक्षक (ग्रेड-3) को तैनात किया गया है, जो ओपीडी में बैठकर ड्यूटी दे रहे हैं।

दूसरी लहर में अप्रैल माह में 6 जिलों में हुई 112 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की मौत

# सागर संभाग में 1 माह में कोरोना से 100 अध्यापकों की हुई मौत

## संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने किया खुलासा

कमलेश तिवारी, सागर

कोरोना की दूसरी लहर में सागर संभाग के 6 जिलों में एक माह में कोरोना से करीब 100 अध्यापकों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 प्रतिशत शिक्षकों ने कोरोना की दहशत के चलते दम तोड़ दिया है। सागर संभाग सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना व निवाड़ी जिले में बीते एक माह में अध्यापक संवर्ग के 112 लोक सेवकों की मृत्यु होने की पुष्टि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने की है। शिक्षा विभाग में सेवारत लोक सेवक की मृत्यु होने पर आश्रितों को तत्काल ही अनुग्रह राशि दिए जाने के शासन स्तर पर निर्देश हैं। बावजूद इसके आश्रितों को अनुग्रह राशि देने में लेटलतीफी और लापरवाही को संयुक्त संचालक शिक्षा ने गंभीरता से लिया है। मृत अध्यापक संवर्ग के आश्रितों को शत-प्रतिशत अनुग्रह राशि देने में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर व निवाड़ी जिले शीर्ष पर हैं। जबकि शेष 4 जिलों में 48 मामले लंबित हैं और अब तक 6 जिलों में 64 प्रकरणों में आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर मनीष वर्मा ने बताया कि सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ जिले में आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान में लेटलतीफी की शिकायतें सामने आ रहीं हैं। आश्रित परिवार को विभिन्न माध्यम से शिकायतें करने के बाद बहुत कठिनाई से राशि

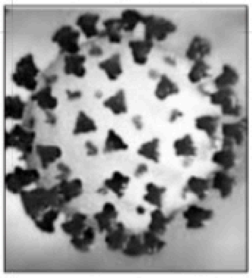

प्राप्त हो रही है, यह निराशाजनक है। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त मप्र ने भी निर्देशित किया है कि विभाग के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसी दिन अनुग्रह राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश के बाद भी संचालनालय में इस संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

## संकुल प्राचार्य और बीईओ होंगे सीधे जिम्मेदार

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने बताया कि माह अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में सागर संभाग के 6 जिलों में अध्यापक संवर्ग के 112 लोक सेवकों की मृत्यु होने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जिसमें जानकारी दी गई है कि करीब 100 अध्यापकों की मृत्यु कोरोना पॉजीटिव होने से हुई है, जबकि 10 से 15 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे भी हैं कि महामारी के इस दौर में तनाव और दहशत में आने से हार्टअटैक सहित अन्य कारणों से भी मृत्यु हुई। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मृत कर्मचारी के आश्रितों को सूचना मिलने के तत्काल बाद 50 हजार की अनुग्रह राशि का भुगतान आश्रितों को किया जाए, जो कि पूर्व में 25 हजार रुपए थी। बावजूद इसके अनुग्रह राशि देने के कई प्रकरणों में लेटलतीफी और लापरवाही बरते जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सागर संभाग में मृत 112 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के प्रकरणों में 64 प्रकरणों को निराकृत कर आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। जबकि 48 प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इन प्रकरणों में यह भी देखने में आ रहा है कि जिस कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उनके आश्रित भी संक्रमित हैं और इलाजरत हैं। इसके अलावा आश्रितों के बैंक खाते सहित अन्य दस्तावेज अपडेट नहीं होने के कारण भी प्रकरण लंबित हैं। जबकि कुछ मामलों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। जेडी श्री वर्मा ने अधिनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सूचना प्राप्त होने के दिन ही अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। वरना राशि नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होने पर संकुल प्राचार्य एवं बीईओ को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार मानकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर कार्यालय से प्राप्त आकड़ों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के 15 कर्मचारियों की एवं निवाड़ी जिला में 6 कर्मचारियों की मृत्यु हुई इनमें से शत-प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए हैं, जबकि सागर जिले में 28 मृत कर्मचारियों में 12 आश्रितों को भुगतान किया गया 16 प्रकरण लंबित हैं। दमोह में 30 प्रकरणों में 14 को भुगतान 16 लंबित, पन्ना जिले में 16 प्रकरणों में 7 में भुगतान 9 प्रकरण लंबित, टीकमगढ़ जिले में 17 प्रकरणों में 10 आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की है, जबकि 7 प्रकरण लंबित हैं।

Badri Gautam

# शिक्षकों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया जाए

ग्वालियर, न.सं.। कोरोना संक्रमण काल में अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षा विभाग के समस्त लोक सेवक, शिक्षक एवं अध्यापक कोरोना की रोकथाम के लिए फील्ड, अस्पतालों, कोविड सेंटरों आदि स्थानों पर फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। राज्य शिक्षक कांग्रेस मध्यप्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राजीव पाठक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर शिक्षकों को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिए जाने की बात कही है। श्री पाठक ने कहा कि ऐसा होने से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं शिक्षकों के परिवारों में सुरक्षा का भाव पैदा हो सकेगा। कोरोना योद्धा घोषित होने पर इन शिक्षकों को 50 लाख की राशि, बीमा लाभ एवं अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उनके परिवारजनों को मिल सकेगा। श्री पाठक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगभग 375 शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी जान गंवा चुके हैं।

Badri Gautam

# कोरोना से मृत शिक्षक, योद्धा करें घोषित

**जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** देश भर में कोरोना महामारी अपने विकराल रूप में है। प्रदेश में अब तक शिक्षा विभाग के अधिकतर शिक्षक कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, शहपुरा विकासखंड के प्राथमिक शिक्षक विश्वास गर्ग का तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। पहले शिक्षक के पिता, फिर माता और अंत में स्वयं शिक्षक विश्वास गर्ग भी कोरोना के प्रकोप से बच न सके। हालात ये है कि भरे पूरे परिवार में अब केवल शिक्षक की पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चे इस आपदा को झेल रहे हैं। राज्य शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का विशेष अभियान चलाया जाए।

राज्य शिक्षक संघ जबलपुर के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि अब तक जिले के जो शिक्षक कोरोना से मृत हो चुके हैं। उनमें से अनेक कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगाई गई डयूटी के दौरान संक्रमित हुए हैं। इसके बाद भी सरकार द्वारा शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा का दर्जा न मिलने के कारण कोई आर्थिक लाभ नही मिला। हालात ये है कि आश्रित परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है।

**तत्काल मिले अनुकंपा:** राज्य शिक्षक संघ जबलपुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पूर्व के मृत और वर्तमान में कोरोना से मृत शिक्षक संवर्ग के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का समयसीमा का विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति प्रदान की जाए।

Badri Gautam

# विद्यार्थियों में असमंजस, मंडल नहीं ले रहा निर्णय

नवदुनिया
खबर पर नजर

**भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)।** माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। परीक्षा जून में होगी, लेकिन समयसारिणी जारी नहीं की गई है। दसवीं की परीक्षा को लेकर तो विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, लिहाजा विद्यार्थी असमंजस में हैं।

हाल ही में मंडल ने आदेश जारी कर परीक्षा एक माह के लिए स्थगित कर दी थी। आदेश में कहा था कि कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेकर शीघ्र अवगत कराया जाएगा। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल एवं एक मई से प्रारंभ होनी थीं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण इन्हें जून में कराने का निर्णय लिया गया। इस साल दोनों परीक्षाओं में प्रदेश भर से करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उधर विगत दिनों स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि 12वीं की परीक्षा अवश्य ली जाएंगी, लेकिन दसवीं परीक्षा के संबंध में एक-दो दिन में निर्णय लिया जाएगा।

## अन्य बोर्ड ने दिया दसवीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन

इसे लेकर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मूल्यांकन किस आधार पर होगा, यह भी तय किया जाएगा। हालांकि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक न तो मंत्री ने कोई निर्णय लिया और न ही मंडल कोई निर्देश जारी कर रहा है। इस संबंध में शिक्षकों का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में जो भ्रम एवं चिंता की स्थिति है उसे मंडल तत्काल दूर करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य राज्यों ने दसवी के विद्यार्थियों के लिए जनरल प्रमोशन का निर्णय ले लिया है तो मप्र बोर्ड भी निर्णय जल्द ले।

# आरजीपीवी में परीक्षा से पहले होगा मॉक टेस्ट

**भोपाल।** राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) करीब चार लाख विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा एक से तीस जून के बीच हो सकती है। परीक्षा से पहले प्रदेशभर के विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण विद्यार्थियों से कोई गलती न हो और बाद में वे परेशान न हों। इसके लिए आरजीपीवी राज्य स्तर पर मॉक टेस्ट कराएगा। इसमें सौ फीसद सफलता मिलने के बाद विवि के संबद्ध कॉलेजों में जून से ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी।

इसके पहले 15 से 30 मई तक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ इंटरनल एग्जाम ऑनलाइन लिए जाने की संभावना है। आरजीपीवी बीई, बीटेक, बीफार्मा और पॉलीटेक्निक के अलावा एमटेक और एमफार्मा प्रथम से अंतिम सेमेस्टर में प्रवेशरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा लेगा। 15 मई से प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। एक से दस जून तक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा, इसके बाद 11 से तीस जून तक शेष परीक्षाएं आयोजित होंगी।

**ऑनलाइन चल रहीं कक्षाएं:** आरजीपीवी के पालीटेक्निक विद्यार्थियों की वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन परीक्षा की सूचना भी दी जाएगी। पहले छठवें, चतुर्थ सेमेस्टर और अंत में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होंगी।

### मोबाइल से भी दे सकेंगे टेस्ट

आरजीपीवी ने विद्यार्थियों के लिए घर बैठे परीक्षा देने की व्यवस्था की है। इसमें विद्यार्थी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल से भी मॉक टेस्ट दे सकेंगे। मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर तत्काल दिखाई देगा। आरजीपीवी 30 जून से रिजल्ट देने की तैयारी में भी है। इसकी शुरूआत अंतिम सेमेस्टर से होगी। इसके बाद शेष परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होंगे।

कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर जून में सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। - **डॉ. सुनील कुमार गुप्ता**, कुलपति, आरजीपीवी

Badri Gautam

**एंकर स्टोरी** दसवीं के नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिल सकते है नंबर

# दसवीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार, नवमीं-ग्यारहवीं के छात्रों को तिमाही-छमाही परीक्षा के आधार पर मिलेंगे नंबर

**शहर प्रतिनिधि, भोपाल** । मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार है। हालांकि दसवीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा निरस्त हो गई है, लेकिन छात्रों को पास करने के स्वरूप पर विभाग अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। वहीं, नवमीं-ग्यारहवीं के छात्रों को तिमाही व छमाही परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। दोनों कक्षाओं का परिणाम पंद्रह मई तक घोषित किया जाएगा।

कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा नवमीं और ग्यारहवीं की फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का नवंबर में मूल्यांकन किया गया था। इसमे तिमाही परीक्षा के रूप में रीविजन टेस्ट व छमाही परीक्षा ली गई थी। अब कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के कारण 9वीं-11वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे दोनों परीक्षाओं के बेहतर परफार्मेंस के आधार पर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार नवमीं के फाइनल परिणाम पांच विषयों में से सर्वश्रेष्ठ के आधार पर जारी किए जाएंगे। यदि वे पांच विषयों में पास होते हैं और कुछ छह विषयों में से एक विषय में फेल हो जाते हैं, तो उन छात्रों को पास घोषित किया दिया जाएगा। एक से अधिक विषयों में 33 फीसदी अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले छात्रों के लिए, अधिकतम 10 ग्रेस मार्क्स अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं और कक्षा 11वीं परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने का ऑप्शन भी उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जो फाइनल परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जो छात्र जिन्होंने नवंबर 2020 या फरवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके है, उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यह मौका कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति में सुधार होने के बाद दिया जाएगा।

Badri Gautam

## सीबीएसई की तर्ज पर दसवीं के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीस अप्रैल से शुरू होने वाली दसवीं की परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग रद्द कर चुका है। अब सिर्फ बारहवीं की परीक्षा होगी। दसवीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, जबकि प्रायवेट विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाए।

दसवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द हो चुकी है। सीबीएसई की तर्ज पर विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए है। जल्द ही इस पर विचार कर दसवीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

**इंदर सिंह परमार**
**राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा मप्र**

# यूपीः पंचायत चुनावों में 577 शिक्षकों की मौत का दावा

## प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा

भास्कर न्यूज़ | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में जारी पंचायत चुनावों में अब तक कोरोना संक्रमण से 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा राज्य शिक्षक संगठन ने किया है, जिसके बाद शिक्षकों और चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों में डर व्याप्त हैं। शिक्षक संघ की ओर से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 2 मई को होने वाली मतगणना टालने की अपील की है। वहीं इस मुद्दे पर सूबे की सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लचर प्रबंधन और कमजोर व्यवस्था का आरोप लगाकर मृत शिक्षकों को मुआवजा देने की मांग की है।

प्रियंका ने कहा है कि 500 शिक्षकों की मौत की खबर दुखद और डरावनी है। शिक्षकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजे और आश्रितों को नौकरी की मांग का मैं समर्थन करती हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार सुरक्षा दे अन्यथा कर्मचारी और शिक्षक मतगणना का बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

Badri Gautam

# एनपीएस में 75 की उम्र तक खाता चलाने का मिलेगा हक

**पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) अमेंडमेंट बिल संसद के मानसून सत्र में पेश होगा। संशोधन के तहत पेंशन सिस्टम में क्या बदलाव किए जा रहे हैं? आइए जानते हैं...**

**▪ 70 साल तक के बुजुर्ग भी खाता खोल सकेंगे**

राष्ट्रीय पेंशन योजना में 70 साल तक के बुजुर्ग भी खाता खोल सकेंगे। फिलहाल यह सीमा 65 वर्ष है । यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ता है तो उसे 75 वर्ष की उम्र तक खाता चलाने और उस पर रिटर्न पाने का अधिकार दिया जाएगा। अभी एनपीएस में 70 वर्ष की अधिकतम आयु तक ही रिटर्न मिलता है।

**▪ तय रिटर्न की गारंटी होगी**

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी पेंशन प्लान होगा। इसके तहत निवेशक को तय रिटर्न की गारंटी होगी। मौजूदा व्यवस्था में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत खाताधारकों मिलने वाली पेंशन लगाए गए फंड से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर होती है द्य

**▪ स्कीम छोड़ने पर अधिक रकम कर पाएंगे इस्तेमाल**

राष्ट्रीय पेंशन योजना में फिलहाल रिटारयमेंट के समय या 60 वर्ष की उम्र हो जाने पर पेंशन फंड में 2 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम रखने पर 40 फीसदी फंड का बीमा कंपनी की तरफ से जारी की गई एन्यूटी में रखना अनिवार्य है।

Badri Gautam

# 15 मई को घोषित किया जाएगा 9वीं और 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम

## अर्द्धवार्षिक और रिवीजन टेस्ट के अंकों से होगा मूल्यांकन

### एक विषय में फेल तो माना जाएगा पास

**भास्कर न्यूज** | सतना ओपन बुक प्रणाली से होने वाली 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त होने के बाद इन कक्षाओं के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन रिवीजन टेस्ट और अर्द्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर किया जाना है, जिसका रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित किया जाना था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अब वार्षिक

परीक्षा परिणाम 15 मई को घोषित किए जाएंगे। 20 मई तक रिजल्ट पोर्टल पर फीड किया जाएगा, ताकि छात्र ऑनलाइन रिजल्ट देख सकें। बताया गया कि कक्षा-9वीं और 11वीं में अध्ययनरत 47 हजार 411 छात्रों के मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में बोर्ड परीक्षा की तरह ही बेस्ट-5 का ऑप्शन दिया गया है।

बताया गया कि शिक्षकों द्वारा परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट-5 के आधार पर की जाएगी यानी विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है और 1 विषय में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो उसे पास घोषित किया जाएगा। एक से अधिक विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे।

## मिलेगा दूसरा मौका

बताया गया कि यदि कोई छात्र कृपांक के अंकों से भी पास नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को उन विषयों की परीक्षा देने के लिए द्वितीय अवसर दिया जाएगा। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना 15 दिन पहले दी जाएगी। यह अवसर उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो अद्र्धवार्षिक परीक्षा एवं रिवीजन टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं।

Badri Gautam

# एनएलआईयू : रिसर्च पेपर के आधार पर होगी परीक्षाएं, 20 प्रतिशत से अधिक नकल मिलने पर प्रोजेक्ट होंगे रिजेक्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं लेने के आदेश जारी किए हैं।

ऐसे में अब नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनवर्सिटी (एनएलआईयू) ने इस बार भी परीक्षाओं को रिसर्च पेपर के आधार पर कराने का निर्णय लिया है। इसमें बीएएलएलबी और एलएलएम के प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ वर्ष के सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएंगी। विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट के आधार पर चार-चार प्रोजेक्ट जमा करना होंगे। इसके साथ उन्हें अपने प्रोजेक्ट से जुडे सब्जेक्ट की केश स्टडी भी देना होगी। इसके बाद विद्यार्थियों का ऑनलाइन वायवा भी लिया जाएगा, जिसके बाद विद्यार्थियों का वैल्यूशन कर रिजल्ट जारी होंगे। कोरोना कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए एनएलआईयू ने शेष विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट वर्क को बढ़ा दिया है। इसके लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। एनएलआईयू के कुलपति डॉ. वी विजयकुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी उसी पैटर्न पर मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन इस बार कई चीजें नई एड की गई हैं। 20 प्रतिशत से अधिक नकल मिलने पर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

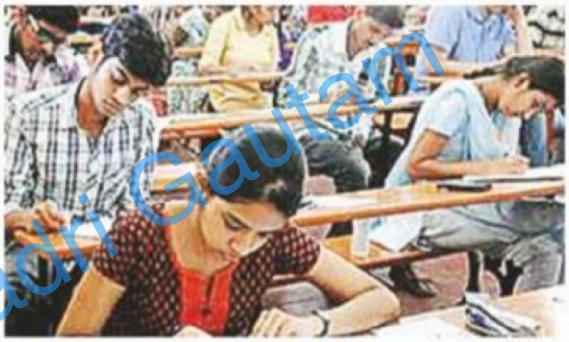

## वैल्यूशन के लिए 15 पैरामीटर तैयार किए

रिसर्च पेपर के आधार पर सेमेस्टर कराने के लिए एनएलआईयू ने 15 पैरामीटर तैयार किए हैं। इसे आधार पर विद्यार्थियों का वैल्यूशन किया जाएगा। पूर्व में थ्यौरी एग्जाम में विद्यार्थियों को 70 अंक और प्रोजेक्ट के तीस अंक दिए जाते हैं। वर्तमान में बदले हुए सिस्टम के मुताबिक उन्हें रिसर्च पेपर के 70 और वायवा में तीस अंक दिए जाएंगे। सभी 15 पैरामीटर पर खरे उतरने के बाद ही विद्यार्थियों को शतप्रतिशत अंक दिए जाएंगे।

Badri Gautam

# शिक्षकों को सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त की 25 प्रतिशत राशि जारी

**भोपाल।** मप्र शिक्षक कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षकों को सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त के 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान शिक्षकों के खाते में कर दिया है। शिक्षक कांग्रेस के सुभाष सक्सेना ने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान इसी माह करने का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में शिक्षक कांग्रेस ने विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया था।

Badri Gautam

# शासकीय आदर्श महाविद्यालय द्वारा भोज विवि की ऑनलाइन कक्षाओं का किया जा रहा संचालन

उमरिया, (नव स्वदेश)। शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया द्वारा मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के रूप में प्राचार्य डॉ अभय पांडेय के निर्देशन में विद्यार्थियों के हितो को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाओं का प्रतिदिन संचालन किया जा रहा है। बीए, बीएससी और बीकॉम की 14 कक्षाएं प्रतिदिन संचालित की जा रही है। महाविद्यालय द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बीए बीएससी तथा बीकॉम का कोर्स मई माह के मध्य तक पूरा हो जाएं। महाविद्यालय में नियुक्त भोज विवि के समन्वयक डॉ. विनय कुमार कुशवाहा ने बताया कि हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि आदर्श महाविद्यालय उमरिया को भोज मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र बनाया गया। इस सत्र 2020-21 में बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की कक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू की गई है। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों के सहयोग से अब तक इस अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित कक्षाओं में अधिक से अधिक छात्र जुड़ कर इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के अनुरूप होने के कारण हर दिन ऑनलाइन कक्षाओं में भोज विवि के अलावा अपने महाविद्यालयों के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे है।

Badri Gautam

## सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए नए पाठ्यक्रम

# नहीं मिल रहे छात्र, तीसरे चरण की बुलाई काउंसलिंग, कई सीटें खाली

### पैरामेडिकल कोर्स में जुड़े इस साल 6 नए पाठ्यक्रम रोजगारपरक हैं सारे कोर्स

### पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और सीटों की स्थिति

| पाठ्यक्रम | अवधि | कुल सीट | रिक्त |
|---|---|---|---|
| माइक्रोबायलॉजी डिप्लोमा | 2 वर्ष | 30 | 19 |
| मेडिकल लैब टेक्नीशियन | 2 वर्ष | 30 | 02 |
| डायलिसिस टेक्नीशियन | 2 वर्ष | 10 | -- |
| पैरा. आप्थैल्मिक असिस्टेंट | 2 वर्ष | -- | 39 |
| एक्सरे टेक्नीशियन | 2 वर्ष | 50 | 35 |
| कैथलैब टेक्नीशियन | 2 वर्ष | 10 | -- |
| गामा कैमरा टेक्नीशियन | 2 वर्ष | 10 | 08 |
| डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नो. | 2 वर्ष | 10 | 01 |
| आर्थो टेक्नीशियन | 1 वर्ष | 20 | 14 |
| ईसीजी टेक्नीशियन | 1 वर्ष | 20 | 14 |
| एनेस्थीसिया टेक्नीशियन | 1 वर्ष | 10 | 03 |
| अल्ट्रा साउंड टेक्नीशियन | 1 वर्ष | 10 | 04 |
| हॉ. मेडिकल रिकार्ड साइंस | 1 वर्ष | 10 | 09 |
| हेल्थ इंस्पेक्टर | 1 वर्ष | 10 | 09 |

जागरण, रीवा

मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की सीटें भर नहीं पा रही हैं। तीसरे चरण की काउंसलिंग बुलाई गई है। अब भी कई सीटें जस की तस पड़ी है। कोई छात्र प्रवेश लेने सामने नहीं आ रहा है। जबकि इसी साल 6 नए पाठ्यक्रम मेडिकल कॉलेज ने नए शुरू किए हैं। नए पाठ्यक्रम रोजगार देने वाले हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण छात्र प्रवेश लेने नहीं पहुंच रहे हैं।

ज्ञात हो कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में अभी तक कई पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित हो रहे थे। इसमें लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस, एक्सरे सहित अन्य पाठ्यक्रम शामिल थे। इन पाठ्यक्रम में 6 और नए कोर्स इस साल से जोड़ दिए गए हैं। इन नए पाठ्यक्रम की शुरुआत कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के निर्देश पर किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने से यहां कार्डियक सर्जरी शुरू हो गई है। ऐसे में दिल से जुड़ी बीमारी और इलाज से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रम को भी तवज्जो दी गई। यही वजह है कि इस वर्ष से 6 नए पाठ्यक्रम को नए सत्र से जोड़ दिया गया है। इसमें दो कार्डियोलॉजी विभाग से, दो कैंसर के इलाज से जुड़े हैं और दो अन्य से संबंधित है। उम्मीद थी कि नए कोर्स जुड़ने से इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। छात्र रोजगार परक कोर्स होने के कारण इसमें रुचि दिखाएंगे। मेडिकल कॉलेज इन पैरामेडिक कोर्स में प्रवेश को लेकर निश्चिंत था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीटों में प्रवेश तो बुलाया गया लेकिन छात्र नहीं मिले। अब तक कई तीन काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। तीसरी फिर बुलाई गई लेकिन छात्र नहीं सामने आ रहे हैं।

### बुधवार को शाम 4 बजे तक था समय

तीसरी काउंसलिंग के लिए बुधवार का समय तय किया गया था। शाम 4 बजे तक अलग अलग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों को आवेदन के लिए समय दिया गया था। सूत्रों की मानें तो तीसरी काउंसलिंग में भी प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कम ही रही। आवेदन उम्मीद से कम ही आए है। इसके पीछे वजह लॉकडाउन और कारोना कर्फ्यू भी मान सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र आवेदन के लिए नहीं पहुंच पाए।

Badri Gautam

# एकलव्य मॉडल विद्यालय चयन परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि आज

**भोपाल (आरएनएन)।** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। संस्था द्वारा राज्यों से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिये शिक्षण स्टॉफ जैसे प्राचार्य (प्रिंसिपल) उप प्राचार्य (वाइस प्रिंसिपल) पीजीटी और टीजीटी की भर्ती के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदक द्वारा आवेदन 30 अप्रैल तक जमा कराये जा सकते हैं। ईटीएसएसई 2021 के लिये ऑनलाइन आवेदन, शैक्षिक योग्यताएँ, शिक्षण अनुभव और अन्य पात्रता मानदण्ड आदि के संबंध में ब्योरे सूचना बुलेटिन पर उपलब्ध हैं।

Badri Gautam

# ऑनलाइन परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट कराएगा आरजीपीवी

**भोपाल( आरएनएन)।** राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानि आरजीपीवी प्रथम से अंतिम सेमेस्टर के करीब चार लाख विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा एक से तीस जून के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए प्रदेशभर के विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा में उन्हें परेशानी ना हो। परीक्षा आनलाइन होने के कारण विद्यार्थियों से कोई गलती नहीं हो, जिसके कारण उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए आरजीपीवी राज्य स्तर पर मॉक टेस्ट कराएगा। शत प्रतिशत सफल होने के बाद राज्य स्तर पर एक जून से आनलाइन परीक्षा ली जाएगी। इसके पहले 15 से 30 मई तक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ इंटरनल एग्जाम होंगे। आरजीपीवी ने बीई, बीटेक, बीफार्मा और पालिटेक्निक के अलावा एमटेक और एमफार्मा प्रथम से अंतिम सेमेस्टर में प्रवेशरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होना है। आरजीपीवी 15 मई से प्रायोगिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन लेगा। एक से दस जून तक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके बाद 11 से तीस जून तक शेष परीक्षाएं आनलाइन आयोजित की जाएंगी।आरजीपीवी के पालीटेक्निक विद्यार्थियों की वर्तमान में ऑलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन परीक्षा की सूचना भी दी जाएगी। पहले छठवें, चतुर्थ और अंत में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होंगी। गत वर्ष आयोजित हुई परीक्षाओं में कई शिकायतें मिलने के बाद इस बार विवि विशेष निगरानी रखेगा।

**1 से 30 जून तक आयोजित होगी परीक्षाएं**

## मोबाइल से भी दे सकेंगे टेस्ट

आरजीपीवी ने विद्यार्थियों के लिए घर से ही परीक्षा आयोजित कर रहा है। इसमें विद्यार्थी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल से टेस्ट देंगे। ऑनलाइन परीक्षा में विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट तत्काल दिखाई देंगे। आरजीपीवी तीस जून से रिजल्ट देने का आगाज करेगा। इसकी शुरूआत अंतिम सेमेस्टर से होगी। इसके बाद शेष परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होंगे।

Badri Gautam

# यूजी-पीजी फाइनल परीक्षा की तारीख तय नहीं

## ओपन बुक पद्धति : शासन के आदेश का इंतजार, 15 जून बाद तक नहीं आसार

**इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** बढ़ते संक्रमण के चलते यूजी-पीजी कोर्स की आफलाइन परीक्षा निरस्त हो चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन ओपन बुक पद्धति से करने का फैसला लिया है। मगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने संक्रमण की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शासन से आदेश मिलने के बाद परीक्षा का कार्यक्रम बनाया जाएगा। वैसे 15 जून तक ओपन बुक पद्धति से भी परीक्षा होना संभव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय अगले कुछ दिनों में उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा-रिजल्ट के मुद्दे पर मार्गदर्शन ले सकता है।

बीए, बीकाम, बीएससी फाइनल ईयर और एमए, एमकाम व एमएससी फाइनल सेमेस्टर की ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाई जानी है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए पेपर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि मई के पहले सप्ताह तक सभी विषयों के ओपन बुक पद्धति से पेपर बन जाएंगे। मगर प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड अभी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ओपन बुक पद्धति से परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन नहीं आई है। माना जा रहा है कि मई के तीसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद है। वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन भी संक्रमण कम होने तक परीक्षा करवाने पर विचार नहीं कर रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 15 जून तक परीक्षा को लेकर कोई आसार नजर नहीं आ रहे है, लेकिन अधिकारियों ने पेपर अपलोड करने के बाद 20-25 दिन में रिजल्ट देने की योजना बनाई है। इस बारे में 10 मई के बाद मूल्यांकन केंद्र को बताया जाएगा। परीक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि परीक्षा से पहले कालेजों को विद्यार्थियों के सीसी नंबर भेजना है।

Badri Gautam

# मंत्रालय से लेकर ब्लॉक में बैठे बाबूओं को समुचित सुरक्षा की दरकार

## लिपिकों ने कहा, वेतन बिल बनाने से लेकर सरकार की 170 योजनाओं का वही करवाते हैं क्रियान्वयन

भोपाल(आरएनएन)। राज्य मंत्रालय से लेकर विकासखंड स्तर तक सरकार की हर योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लिपिक संवर्ग ने महामारी संक्रमण में समुचित सुरक्षा की जरूरत बताई है। इनका कहना है कि कार्यालयों में कोई सुरक्षा नहीं है। नतीजतन संक्रमण के साथ.साथ मौत हर पल उनके सामने खड़ी हुई है। प्रदेश के लिपिक संवर्ग ने वर्ष 1989 से लेकर अभी तक कि अपनी संघर्ष गाथा बताई है। इनका कहना है कि 1989 में प्रदेश में बाबुओं की संख्या सवा लाख हुआ करती थी। जबकि मात्र उस दौर में 11 योजनाओं का संचालन होता था। आज राज्य सरकार की 170 योजनाएं हैं जबकि बाबूओं की संख्या मात्र 35000 बची हुई है। इन्होंने कोरोना संक्रमण काल में काम करते हुए अपनी अनेक परेशानियां सरकार के समक्ष बताई है। बाबूओं का कहना है कि वेतन बिल बनाने से लेकर सभी योजनाओं का समय से क्रियान्वयन हो। इसके लिए लगातार पत्रों का जारी करना उनके कंधों पर ही है। समय से योजनाओं से संबंधित फाइलें तैयार करके अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य भी वही करते हैं। अन्य जनकल्याणकारी कार्यों के दस्तावेज उन्हीं को बनानी पड़ रहे हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है।

### प्रदेश में कई बाबुओं की हो चुकी है मौत: मनोज बाजपेई

मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बाजपेई का कहना है कि कोरोना के इस संकटकाल में हमारे कई साथियों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय से लेकर सतपुड़ा विंध्याचल संभाग जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर बाबू संक्रमण का शिकार होकर मौत के आगोश में समा चुके हैं। इसके बावजूद ना तो उनके लिए वैक्सीन का टीका लगवाने की व्यवस्था की गई है ना ही राज्य सरकार ने इन्हें अभी तक कोरोना योद्धा माना है। अब जो बाबू दिवंगत हो गए हैं उनके परिवारों को सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं है।

### सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री को लिखा जाएगा पत्र: सुधीर नायक

मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक का कहना है कि प्रदेश में बाबू को संचित सुरक्षा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में 10 प्रतिशत उपस्थिति होने के बाद भी अधिकारी बाबू को लगातार बुला रहे हैं। कारण भी है कि समय से वेतन बिल तैयार होना है। इसके अलावा हर दिन राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर हो रहे आदेशों को बाबू ही बनाकर तैयार करते हैं। इस कारण इन्हें सुविधाएं और सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी है।

Badri Gautam

# जन शिक्षक राजेश पाण्डेय का निधन

रीवा(नव स्वदेश)। जनशिक्षा केंद्र मार्तण्ड क्रमांक-3 में पदस्थ जन शिक्षक राजेश पाण्डेय का संजय गांधी अस्पताल में बुधवार की रात निधन हो गया। स्व.पाण्डेय विगत 10 दिनों से अस्वस्थ थे। वह करोना बीमारी से संक्रमित हो गए थे । पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही परिजनों द्वारा संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया जहां कल रात 9 बजे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । उनकी पत्नी अल्का पाण्डेय शा.उ.मा.वि.गोड्डर में अध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। एक मात्र पुत्र था जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। जैसे ही राजेश पांडेय के मौत की खबर लगी शिक्षा विभाग शोकाकुल हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी के.पी तिवारी, रमसा प्रभारी पी.एल.मिश्रा,संजय सक्सेना, रीवा बीईओ आरएल दीपांकर, बीआरसीसी रीवा प्रवीण शुक्ल, प्राचार्य रहट रवि नारायण वर्मा, बीएसी उमेश गौतम, राजेन्द्र यादव, अश्विनी सिंह, जन शिक्षक आराधना पांडेय, रीना मिश्रा, अनुज पटेल, बालकृष्ण पाण्डेय, शिक्षक जीतेन्द्र चतुर्वेदी, सँजय द्विवेदी, सँजीव दुवे, वीरेंद्र शुक्ला, राजेश सिंह सहित समूचे शिक्षा विभाग ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति एवं परिवार को इस संकट सहने की ईश्वर शक्ति दे ऐसी कामना की है।

## बेटे के सदमे को नही सह पाये पिता,हुई मौत

आज से दस दिन पूर्व जिस घर में खुशी का माहौल था आज उस घर में करूण रूदन माहौल को गमगीन कर रहा है। बेटे के मृत्यु की खबर सुनने के बाद पिता खुद को नही संभाल पाये और उनका भी निधन हो गया। सूत्रों का बताना है कि राजेश पाण्डेय के पिताश्री का गुरूवार की शाम 4 बजे के लगभग मृत्यु हो गयी। इस घटना की खबर दिल को दहला देने वाली रही।

Badri Gautam

**नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा : प्रदेश में छह वर्ष से कम उम्र की मात्र 64% बालिकाएं ही जा रहीं स्कूल**

# बालिका शिक्षा में मध्यप्रदेश देशभर में 25वें नंबर पर

**प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र की करीब 64 फीसदी बालिकाएं ही स्कूल जा रही हैं, इस मामले में मध्यप्रदेश देश में 25वें नंबर पर है।**

भोपाल/ग्वालियर • **डीबी स्टार**

छह वर्ष से कम उम्र की ज्यादातर बालिकाएं स्कूल पढ़ने नहीं पहुंच पा रही हैं इस बारे में जब डीबी स्टार टीम को पता चली तो उसने पड़ताल के लिए नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट खंगाली। इस रिपोर्ट के अध्ययन से खुलासा हुआ कि प्रदेश में बालिकाएं शिक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है। खास बात यह है कि इस मामले में पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ 22 वें स्थान पर है। वहीं, सबसे बेहतर स्थिति केरल की है। जहां 95.4 फीसदी बच्चियां स्कूल गई हैं। वहीं, सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है। जहां सिर्फ 54 फीसदी बच्चियां ही स्कूल गई हैं। जबकि राष्ट्रीय औसत इस मामले में 68.8 फीसदी है, लेकिन अपना मध्य प्रदेश इससे पांच फीसदी पीछे है। शासन-प्रशासन द्वारा बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे सारे अभियान और योजनाओं का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है और स्थिति नहीं सुधर रही है।

### राज्यवार शिक्षित बालिकाओं का प्रतिशत

| राज्य | शिक्षित बालिकाएं | राज्य | शिक्षित बालिकाएं | राज्य | शिक्षित बालिकाएं |
|---|---|---|---|---|---|
| केरल | 95.4 | हिमाचल प्रदेश | 79 | ओडिशा | 67.8 |
| मिजोरम | 91.2 | महाराष्ट्र | 77.4 | छत्तीसगढ़ | 67.6 |
| गोवा | 85 | तमिलनाडु | 77.2 | अरुणाचल प्रदेश | 67.1 |
| अंडमान निकोबार | 84.7 | पंजाब | 76 | जम्मू कश्मीर | 65.6 |
| मेघालय | 83 | असम | 75 | मध्य प्रदेश | 64 |
| त्रिपुरा | 81.9 | पश्चिम बंगाल | 74 | उत्तर प्रदेश | 63 |
| मणिपुर | 81.7 | उत्तराखंड | 72.7 | तेलंगाना | 62.2 |
| दिल्ली | 81.7 | गुजरात | 72 | आंध्र प्रदेश | 62 |
| नागालैंड | 81 | कर्नाटक | 70.7 | झारखंड | 61.1 |
| सिक्किम | 79.7 | हरियाणा | 70.3 | राजस्थान | 57.2 |

### 100 फीसदी तक शिक्षण का है लक्ष्य

*केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। साथ ही करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। वहीं, सभी राज्यों को 100 फीसदी तक शिक्षण व्यवस्था करने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन देशभर में एक भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है।*

### राष्ट्रीय औसत से भी 5% पीछे

*रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में जहां देश का राष्ट्रीय औसत 68.8 फीसदी है, जबकि मध्यप्रदेश का औसत इस मामले में 64 फीसदी ही है यानि हमारा प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी लगभग पांच फीसदी पीछे चल रहा है। जबकि यहां तमाम योजनाओं के बेहतर संचालन करने का दावा किया जाता है।*

Badri Gautam

# यूटीडी और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस, संस्थान 30 मई तक बंद करने की तैयारी

## ऑनलाइन कोर्स की 15 मई तक ऑनलाइन ही समीक्षा

भास्कर संवाददाता | इंदौर

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते उच्च शिक्षा विभाग 30 मई तक कॉलेज पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम 2020 में बनाया गया था, उससे पढ़ाई जारी रहेगी। 15 मई तक इसकी समीक्षा भी होगी। इधर, सारे सरकारी कॉलेजों के साथ ही यूटीडी में भी ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट जारी हैं। सभी 31 टीचिंग विभाग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यह सिलसिला पूरे मई माह जारी रहेगा। संभवतः जून के पहले सप्ताह में नए सिरे से समीक्षा कर आगे की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉ. चंदन गुप्ता का कहना है कि यूटीडी पूरी तरह बंद है, लेकिन सारे विभागों में सारे कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं।

Badri Gautam

## पिछले माह लिया था निर्णय

पिछले माह की शुरुआत में इंदौर में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ना शुरू हुआ था। ऐसे में विभाग ने पहले 31 मार्च और फिर 15 व 30 अप्रैल तक कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया था। तब कहा गया था कि छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई जारी रहेगी। शुरुआत में कुछ कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से नहीं लिया। अब सारे कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है।

जूनियर सेल्समैन भर्ती... सहकारिता विभाग में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के साथ अन्याय

# पहले अपात्र आवेदकों को चुन लिया अब मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप

## आवेदन में अपलोड दस्तावेज और मूल दस्तावेज में अंतर होने पर उम्मीदवार की दावेदारी निरस्त

*उम्मीदवार को हासिल अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। दो या अधिक उम्मीदवार के समान अंक होने पर हायर सेकंडरी में अधिक अंक लाने वाले को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार यह नियम कामर्स में स्नातक और अधिक आयु वाले उम्मीदवार पर लागू होगा। चयन समिति द्वारा मेरिट वाले उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान आवेदन में अपलोड दस्तावेज और मूल दस्तावेज में अंतर होने पर उम्मीदवार की दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी। बताया जाता है कि चयनित उम्मीदवार को प्रति दुकान 8400 रुपए प्रतिमाह देय कमीशन में से 6000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।*

मेरा कॅरियर

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

सहकारिता विभाग में सरकारी नौकरी की आस लगाए नौजवानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले ढाई साल से इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई नया पेंच सामने आने से नियुक्ति को टाल दिया जाता है। ताजा मामला चयन प्रक्रिया के बाद तैयार की गई मेरिट लिस्ट का है। कई आवेदकों का आरोप है कि लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने पहले तो अपात्र उम्मीदवारों का चयन कर लिया। इसे लेकर जब शिकवा-शिकायत हुई तो आवेदकों से दावे-आपत्तियां बुलवाई गईं, लेकिन उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। चयन से वंचित आवेदकों का कहना है कि विभाग वेटिंग लिस्ट में शामिल परीक्षार्थियों को चयन का मौका नहीं दे रहा है। यानी अपात्र बाहर हो भी गए तो पात्र उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सकेगा। इस विसंगति को लेकर परीक्षार्थी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ऐसी भर्ती का क्या मतलब जिसमें सैकड़ों पद बेवजह खाली रह जाएं।

## क्या है मामला

प्रदेश भर की प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं में सेल्समैन के 3629 पद भरे जाना हैं। इसके लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मंगाए थे। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर किया गया। आवेदनों की छंटनी और मेरिट लिस्ट तैयार करने में भी लगभग डेढ़ साल का समय लग गया। 3629 पदों के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट 20 मई 2020 को जारी हुआ। कोरोना काल के कारण विभाग ने चयन प्रक्रिया सालभर रोके रखी। 1 फरवरी से 2021 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। 4 फरवरी तक दावे-आपत्ति बुलाई गईं। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेशभर से 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन दो महीने के बाद भी विभाग ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है। नतीजतन, मामला जस का तस ही अटका हुआ है।

### 200 रुपए फीस वसूली गई

आवेदन के लिए उम्मीदवारों से 200 रुपए फीस वसूली गई। वहीं उसमें संशोधन करने पर अलग से 50 रुपए चार्ज निर्धारित था। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकारी राशन दुकान, कृषि, साख, फसल उपार्जन केन्द्रों पर होनी है।

### फैक्ट फाइल

- 14 से 28 सितंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए।
- 30 सितंबर 2018 आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख।
- 150 कुल अंक मेरिट लिस्ट के लिए।
- 6000 रुपए मानदेय निर्धारित, 200 रुपए परीक्षा शुल्क वसूला।

सीधी बात — **अरविंद सेंगर,** ज्वाइंट कमिश्नर, सहकारिता

## 1800 दावे-आपत्तियां आई हैं कमेटी कर रही उनका परीक्षण

**जूनियर सेल्समैन के पदों पर नियुक्ति का मामला दो महीने से लंबित क्यों है?**
-विभाग में कोई न कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकल रहा है जिससे काम ठप है। फिलहाल मेरे सहित चार प्रमुख लोग पॉजिटिव हैं।

**कितने मामलों को लेकर दावे-आपत्तियां आई हैं और कब तक उनका निराकरण करेंगे?**
-करीब 1800 आवेदकों ने दावे-आपत्तियां लगाई हैं। निराकरण का फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर केस की सुनवाई अलग-अलग होगी।

**स्थानीय प्रतिभागियों के बजाय बाहरी उम्मीदवारों का चयन होने की भी शिकायत है?**
-हां, सबसे अधिक शिकायतें इसी मामले की ही है। कमेटी इनका परीक्षण कर रही है। गैर स्थानीय सहित विभिन्न कारणों से अपात्र साबित होने वाले उम्मीदवार का चयन निरस्त करेंगे।

**वेटिंग लिस्ट वाले पात्र उम्मीदवारों को लेने से मना क्यों किया जा रहा है?**
-हमने कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। कोई प्रतिभागी खुद को वेटिंग वाला मानता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

**अपात्र के प्रक्रिया से बाहर होने पर यदि स्थानीय को मौका नहीं मिलेगा तो पद रिक्त रह जाएंगे?**
ऐसा नहीं होगा। हम परीक्षण के बाद पात्र प्रतिभागी रखेंगे, लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट के चक्कर में न पड़े।

Badri Gautam

# इंडियन पोस्ट सर्विस की रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू

**सिटी रिपोर्टर**|इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की है। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 2428 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी विषय के साथ 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स 26 मई तक https://indiapost.gov.in या https://appost.in/gdsonline पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Badri Gautam

# विभागों के कर्मचारियों को इलाज के लिए मिलें 3 लाख

भोपाल| कई कर्मचारी संघों ने मांग की है कि बिजली कंपनी की तरह अन्य विभागों के निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी कोविड-19 के इलाज के लिए 3 लाख एडवांस दिया जाना चाहिए। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कर्मचारी कांग्रेस के महामंत्री आदर्श शर्मा ने कहा है कि दुग्ध संघ समेत अन्य सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी संकट के इस दौर में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। सैकड़ों कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। सभी को इलाज के लिए 3 लाख दिए जाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य कर्मचारी संगठन इस तरह की मांग पहले कर चुके हैं।

Badri Gautam

# क्लैट परीक्षा नहीं होगी पोस्टपोंन

सिटी रिपोर्टर | कोविड-19 के कारण जिस तरह सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, ऐसे में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) को भी स्थगित करने को लेकर स्टूडेंट्स में हलचल बनी हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुलपति और क्लैट कंसॉर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष फैजान मुस्तफा ने बताया कि क्लैट 13 जून को निर्धारित है। सरकार ने 1 जून को सीबीएसई 12वीं परीक्षा की नई तारीखें घोषित करने का ऐलान किया है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं 15 जून के पहले शुरू नहीं होंगी। 13 जून को क्लैट होने से बोर्ड से तारीख नहीं टकराएगी।

Badri Gautam

# नवोदय एंट्रेंस एग्जाम दूसरी बार टला

**सिटी रिपोर्टर** | नवोदय विद्यालय समिति ने एक बार फिर क्लास 6वीं के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट-2021 स्थगित कर दिया है। जो स्टूडेंट्स 16 मई 2021 को होने वाले एडमिशन टेस्ट में बैठने वाले थे, वे अभी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम से जुड़ा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यह दूसरा मौका है, जब नवोदय एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोंड हो रहा है। इससे पहले यह एग्जाम 10 अप्रैल को होना था, जिसे बाद में 16 मई तक आगे बढ़ा दिया गया था। इस परीक्षा के लिए 30 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था।

Badri Gautam

### कोरोना के कारण दस प्रतिशत कर्मचारी ही आ रहे कार्यालय, जिलों के ऑफिस बंद जैसे

# ऑफिसों में ठहर गईं रोज की सवा लाख फाइलें

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425174141

कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यालयों में उपस्थिति दस प्रतिशत करने के बाद से प्रदेश में पंचायत से मंत्रालय तक हर दिन औसतन सवा लाख फाइलों और नोटशीटों का मूवमेंट ठहर गया है। इससे राज्य मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे बड़े कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। मंत्रालय हर दिन औसतन चार हजार आते थे।

मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल में स्वास्थ्य, वन, लोक निर्माण, खनिज, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह, वित्त, जल संसाधन, राजस्व और आदिम जाति कल्याण से संबंधित हर दिन लिपिक से लेकर प्रमुख सचिव तक 200 से अधिक फाइलें इधर से उधर होती हैं और नोटशीट लिखी जाती हैं। अब ये फाइलें टेबिलों पर ढांककर या फिर अलमारियों में बंद कर दी गई हैं।इन विभागों में ज्यादा होता है काम

भोपाल स्थिति पर्यावास भवन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, निर्माण भवन, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, राहत कार्यालय, पंचायतराज संचालनालय, विकास आयुक्त, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य मंडी बोर्ड, कोष एवं लेखा कार्यालयों में ज्यादा फाइलें घूमती हैं। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर में स्थित वाणिज्यिक और आबकारी कार्यालय अलग हैं।

Badri Gautam

### कहां कितनी फाइलों का होता है मूवमेंट (अनुमान)

| | |
|---|---|
| 22800 ग्राम पंचायत | 1,14000 (प्रति पंचायत पांच) |
| 313 जनपद पंचायत | 15,650 (50 फाइल प्रति जनपद) |
| 52 जिला पंचायत | 5,200 (100 फाइल रोज) |
| 52 कलेक्टर कार्यालय | 7,800 (150 प्रति जिला) |
| 10 संभाग आयुक्त कार्यालय | 2,000 (200 प्रति संभाग) |
| 52 विभाग प्रमुख कार्यालय | 10,400 (200 प्रति विभाग) |
| 52 राज्य कार्यालय मंत्रालय | 10,400 (200 प्रति विभाग) |
| कुल अनुमान | 1,65,450 |

### कर्मचारियों की जान पर बनी है

मंत्रालय के तीन कर्मचारियों का संक्रमण के बाद निधन हो चुका है। 60 से अधिक कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने राज्य स्तरीय कार्यालयों को 15 मई तक पूरी तरह बंद करने की मांग की है।

# मैथमेटिक्स में कॅरियर और रोजगार के अवसरों की वेबटॉक में दी गई जानकारी

पीपुल्स संवाददाता ● संत नगर

मो.नं. 8602467816

संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज के गणित विभाग ने ट्रिक्स आफ कॅरियर अपॉर्चुनिटी इन मैथमेटिक्स पर वेबटॉक आयोजित की।

इस मौके पर शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के एसो. प्रोफेसर डॉ. संदीप कुमार मल्होत्रा ने गणित के ट्रिक्स और गणीतीय क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में छात्राओं को बताया। उन्हें रोजगार के विभिन्न तरीके विकसित करना बताया। प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि हम इस महामारी में निरंतर प्रयासरत हैं कि छात्राओं को ज्ञानार्जन के साथ विषय से जुड़े रोजगार की भी जानकारी हो। डॉ. मल्होत्रा ने कहा कि वैदिक गणित तकनीकी संग्रह है। इसका उपयोग अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति तथा गणना में किया जाता है। उन्होंने वैदिक गणित में समुच्चय, यावदूनम, संकलन, व्यवकलनाभ्याम आदि विधियों के उदाहरण दिए। इन विधियों के माध्यम से बच्चों को गणित में रुचि जाग्रत करने के लिए प्रेरित किया।

Badri Gautam

# कॉलेजों ने कमियां दूर नहीं की, तो सीटों में होंगी कटौती

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

सरकारी, प्राइवेट इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब एआईसीटीई ने नियमों का पालन नहीं करने पर कॉलेज और पॉलीटेक्निक के सत्र 2021-21 की सीटों में कटौती करने का निर्णय लिया है। कमियों की पूर्ति के लिए एआईसीटीई ने 30 जून तक समय दिया है। प्रदेश में सागर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर और नौगांव सहित एक दर्जन इंजीनियरिंग और 69 पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं। एआईसीटीई ने गत वर्ष एक्शन लेते हुए सीटों में कटौती कर दी थी, लेकिन शासन ने एक साल में मापदंडों की पूर्ति का पत्र भेजकर सीटों को बचा लिया था। अभी तक वे अपनी खामियों को दूर नहीं कर पाए हैं। इसलिए एआईसीटीई चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने पत्र जारी कर कहा है कि मापदंडों का पालन नहीं करने पर संस्थानों की कुल सीटों में कटौती की जाएगी।

**न फैकल्टी है और न सुविधाएं:** इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक कॉलेजों में 48 से 58 फीसदी वैकेंसी बनी हुई है। इसके अलावा क्लास रूम, लैब, उपकरण, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और अधोसंरचना की कमियों को समय रहते शासन द्वारा पूरा नहीं किया गया, तो कॉलेजों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

> इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। 30 जून तक का समय है, उसके बाद मापदंड पूरे नहीं मिले सीटों में कटौती की जाएगी। -**अनिल सहस्त्रबुद्धे**, चेयरमैन, एआईसीटीई

Badri Gautam